आरक्षित निर्णय

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान और माननीय न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा

दाण्डिक अपीलीय संख्या : 119/ 2015

निर्णय आरक्षित करने की तिथि: 21.09.2021
निर्णय घोषित किये जाने की तिथि : 10.11.2021

धर्मपाल सिंह यादव @डीपी यादव

....अपीलकर्ता

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो

...प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए वकील :श्री सुरेन्द्र सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री एस. आर. एस.

प्रतिवादी के वकील:श्री संदीप टंडन विद्वान अधिवक्ता के साथ सुश्री तेजस्विना सागर ।

न्यायालय ने निम्नलिखित किया:

निर्णय :(माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के अनुसार)

तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), देहरादून द्वारा दिनांक 10.03.2015 को पारित निर्णय से व्यथित, अपीलकर्ता, धर्मपाल सिंह यादव उर्फ डी. पी. यादव ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है।

2. उक्त निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की खंड 302 के साथ पठित (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की खंड 302 से अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।उन्हें आगे 1,00,000/- रुपये का जुर्माना भरने और जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है।वह 2 वर्ष के थे

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 307 से, जो 120-बी के साथ पठित है, अपराधों के लिए दोष् सिद्ध किया गया अग्रेतर दस वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया।उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना अदा न करने करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया।इसके अलावा, उखंड भारतीय दंड व्यतिक्रम की धारा 326 के साथ पठित 120-बी के से अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने और चूक होने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है।सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि 13.09.1992 को अनिल कुमार भाटी (पी. डब्ल्यू. 39), मृतक व्यक्ति में से एक महेंद्र सिंह भाटी के भतीजे ने पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक लिखित रिपोर्ट (एक्स. का. 30) दर्ज की, जिसमें उसने दावा किया कि 13.09.1992 को लगभग 6: 30, विधायक महेंद्र सिंह भाटी, दादरी निर्वाचन क्षेत्र, गाजियाबाद को मूलचंद तिवारी, इंस्पेक्टर सी.बी.सी.आई.डी. ने महेंद्र सिंह भाटी को टेलीफोन द्वारा मूल चन्द तिवारी को सूचित किया कि उनका बयान संतराम की हत्या के मामले में बयान दर्ज करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है इसलिए, उसे भंगल गांव आने का निर्देश दिया जाता है। इस सूचना पर महेंद्र सिंह भाटी अपने ड्राइवर देवेंद्र और गनमैन वेदराम कौशिक (पी. डब्ल्यू. 31) के साथ अपनी मारुति कार में गांव के लिए रवाना हो गए भंगल। रास्ते में उनका दोस्त उदय राम आर्य भी कार में बैठा और पीछे की सीट पर बैठ गया। यद्यपि जैसे ही दादरी रेलवे क्रॉसिंग गेट, भांगेल गांव के रास्ते में, बंद हो गया, महेंद्र सिंह भाटी की कार रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रुक गई।शिकायतकर्ता के अनुसार, वह और धर्मवीर सिंह भी अपनी मोटरसाइकिल पर रेलवे क्रॉसिंग गेट पर पहुंचे।जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग गेट खोला गया, लगभग 7:00 बजे और जैसे ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, करीब सात से आठ अज्ञात लोगों ने कार पर गोलियां चला दीं।इससे महेंद्र सिंह भाटी और उदय प्रकाश आर्य की मौके पर ही मौत हो गई।बंदूकधारी वेदराम कौशिक (पी डब्ल्यू 31) भी घायल हो गए।फायरिंग शुरू होते ही चालक देवेंद्र फरार हो गया।महेन्द्र सिंह भाटी की कार के पास एक अन्य कार में ओ. पी. कयाल (पी.इसके अलावा,

अपनी साइकिल पर रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास खड़ा धर्मवीर सिंह भी घायल हो गया। पी. ओ. पी. कयाल (पी. डब्ल्यू. 35) को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, बंदूकधारी वेदराम कौशिक (पी. डब्ल्यू. 31) को नरेंद्र मोहन अस्पताल ले जाया गया, साइकिल सवार धर्मवीर सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के बाद हत्यारे एक मारुति कार में बैठ गए और फरार हो गए।जब वे भाग रहे थे, तो वे चिल्ला रहे थे कि " प्रकाश पहलवान को चुनाव लड़ने के लिए फिर से प्रयास करें " शिकायतकर्ता के अनुसार, अमर सिंह, ओमवीर सिंह, मनवीर सिंह, घटनास्थल पर खड़े प्रकाश, अतर सिंह, धर्मवीर सिंह और अन्य लोगों ने घटना को देखा है। हालांकि, इन चश्मदीदों ने हमलावरों को पहचाना है, लेकिन इस डर के कारण कि हमलावर सशस्त्र थे, उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की।

4. शिकायतकर्ता अनिल कुमार भाटी (डाक टिकट 39) ने सिकंदराबाद के एम. एल. ए. नरेन्द्र सिंह भाटी (डाक टिकट 10) को शिकायत (पूर्व का.शिकायत (एक्स. का. 30) पुलिस स्टेशन दादरी, गाजियाबाद में दर्ज की गई थी।इस शिकायत (एक्स. का. 30) के आधार पर, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 147,148,149,302 और 307 के से अपराधों के लिए एक औपचारिक प्राथमिकी (एक्स. का. 39), अर्थात् प्राथमिकी संख्या 371/92 दर्ज की गई थी।

5. प्रारंभ में, जांच एस. एस. आई., जगदीश सिंह (पी. डब्ल्यू. 21) को सौंप दी गई थी।जांच अधिकारी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और वहां से एके-47 राइफल के पांच खाली कारतूस और 7.62 एमएम राइफल के सात खाली कारतूस बरामद किए।रिकवरी मेमो (एक्स. का. 96) द्वारा से, महेंद्र सिंह भाटी और उदय प्रकाश आर्य के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

6. चूंकि वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह भाटी की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, इसलिए उनकी हत्या ने पर्याप्त गर्मी पैदा कर दी।लेकिन चूंकि पुलिस द्वारा की गई जांच सही नहीं थी, इसलिए 10.08.1993 को 5

यह जांच अधिसूचना संख्या 228/58/92 ए. बी. डी. द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में सीबीआई) को हस्तांतरित की गई थी।

7. प्रारंभ में, सीबीआई ने भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 147,148,149,302,307,109,120-बी और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में टाडा) की खंड 3 से अपराधों के लिए आर. सी.-1 (एस)/93/एस. आई. यू.-1 के रूप में मामला दर्ज किया।

8. जांच के दौरान, सीबीआई ने टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत महाराज सिंह और औलाद अली के इकबालिया बयान दर्ज किए। जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने न केवल वर्तमान अपीलार्थी, धर्मपाल सिंह यादव @ डी.पी. यादव, बल्कि अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् करण यादव, तेजपाल भाटी, प्रणीत भाटी, महाराज सिंह, पाल सिंह @पाला @लक्कर @ हरपाल सिंह, जयपाल गुर्जर और औलाद अली ।

9. प्रारंभ में, दिनांक 07.01.1996 के आदेश द्वारा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, देहरादून ने अभियुक्त, धर्मपाल सिंह यादव, करण यादव, प्रणीत भाटी, महाराज सिंह, तेजपाल भाटी, औलाद अली के अग्रेतर भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 302,307,326 से अपराधों के लिये विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आगे संज्ञान लिया । पाल सिंह उर्फ पाला उर्फ हरपाल सिंह और जयपाल गुर्जर के विरुद्ध भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 302,307,326 और शस्त्र अधिनियम की खंड 27 के से आरोप तय किए गए हैं।

10. चूंकि अपीलकर्ता उक्त संज्ञान आदेश सय पीड़ित था, इसलिए उसने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत एक आपराधिक विविध याचिका दायर की।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में अपीलार्थी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।इसके बाद, दिनांक 22.04.2000 के आदेश द्वारा, इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी, और उसके विरुद्ध अभियोजन को रद्द कर दिया।

11. चूंकि सीबीआई दिनांक 22.04.2000 के आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी।माननीय उच्चतम

न्यायालय ने दिनांक 26.09.2001 के आदेश द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2000 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया। नतीजतन, दिनांक 30.03.2001 के आदेश द्वारा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, देहरादून ने अपीलकर्ता का मामला विशेष न्यायाधीश, सीबीआई को सौंप दिया, यह मामला सत्र विचारण संख्या 48/2001 के रूप में दर्ज किया गया था।

12. चूंकि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों का आदेश एक भिन्न सेशन मामले से किया जा रहा था, इसलिए दिनांक 23.04.2001 के आदेश द्वारा विशेष न्यायालय, सीबीआई ने सेशन को समेकित किया। विचारण नं. 87/ 2000, सी. बी. आई. बनाम तेजपाल भाटी और अन्य" को सेशन विचारण संख्या 48/ 2001 , **" सी. बी. आई. बनाम डी0 पी 0 यादव "** के साथ समिलित करने के आदेश किया । डी. पी. यादव।

13. अपने मामले को साबित आदेश के लिए सीबीआई ने 41 गवाहों से पूछताछ की, 115 दस्तावेज प्रस्तुत किए और 159 वस्तुएं पेश कीं।

14. विचारण के दौरान चार सह-अभियुक्त व्यक्तियों महाराज सिंह, तेजपाल भाटी, जयपाल गुर्जर और औलाद अली की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए विद्वान साक्ष्य की सराहना करने के पश्चात दिनांक 10.03.2015 के एक आम फैसले द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उपर्युक्त के रूप में सजा सुनाई.अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा कई अपीलें दायर की गई हैं।लेकिन वर्तमान में हम अपीलकर्ता, डी. पी. यादव द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहे हैं.अन्य अपीलों पर अलग से फैसला किया जाएगा।

15. श्री सुरेन्द्र सिंह, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैंः- -

(क) अनिल कुमार भाटी (पी. डब्ल्यू. 39) द्वारा सात या आठ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायत (एक्स. का.-30)कथित शिकायत में, अनिल कुमार भाटी (पी डब्लू 39), अपीलकर्ता या किसी अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति पर कोई संदेह नहीं डालता है.

(ख) यद्यपि अनिल कुमार भाटी (अ. सा. 39) घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है, उसकी शिकायत (पूर्व का. 30) और धारा 161 के तहत उसका बयान, दोनों किसी भी ठोस विवरण से वंचित हैं।हालांकि वह दावा करते हैं कि सात से आठ लोगों ने मृतक पर हमला किया, लेकिन वह कथित हमलावरों की विशेषताओं या विवरण का वर्णन नहीं करते हैं।उन्होंने उनके पास मौजूद हथियारों का भी जिक्र नहीं किया।यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक है क्योंकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि एक एके-47 बंदूक का इस्तेमाल किया गया था।एके-47 कोई साधारण हथियार नहीं है, जिसे कोई भी चश्मदीद भूल जाए।इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि हमलावर दो कारों में भाग गए।फिर भी, वह न तो कारों के रंग का उल्लेख करता है, न ही कारों की कंपनी और न ही कार के पंजीकरण नंबरों का उल्लेख करता है।उसका सामान्य और घटना का अस्पष्ट विवरण, विशेष रूप से जिसमें उसके चाचा महेंद्र सिंह भाटी की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी, अपराध संदिग्ध के स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।

(ग) अपनी शिकायत (एक्स. का.-30) में अनिल कुमार भाटी (पी. डब्ल्यू. 39) ने मात्र यह कहा है कि हमलावर एक मारुति कार में छोड़ गए थे।शिकायतकर्ता द्वारा 'मारुति कार' जैसे सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के बाद से ही अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता, कार और कथित अपराध के बीच कोई संबंध साबित करने में विफल रहा है।

(घ) अभियोजन पक्ष ने एक झूठी कहानी बनाई है कि महेंद्र सिंह भाटी की हत्या एक गिरोह के सतबीर गुर्जर और महेंद्र सिंह फौजी के एक अन्य गिरोह के बीच हुए गिरोह युद्ध के कारण हुई थी।अभियोजन पक्ष का मानना था कि दादरी के वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह भाटी ने सतबीर गुज्जर के गिरोह को संरक्षण दिया था जबकि अपीलकर्ता डी. पी. यादव ने महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह को संरक्षण दिया था।यह इस गिरोह युद्ध के कारण है कि अपीलकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि महेंद्र सिंह भाटी को किराए के हमलावरों द्वारा मार दिया जाए।लेकिन एक विस्तृत कहानी गढ़ने के बावजूद

अभियोजन पक्ष इस कहानी के मूल तत्वों को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

(ई) अभियोजन पक्ष ने मृतक महेंद्र सिंह भाटी और अपीलकर्ता के बीच एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी दावा किया है, जिसने अपीलकर्ता को पहले वाले से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया है।लेकिन यह दावा भी अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा समर्थित नहीं है।क्योंकि, मृतक के पुत्र समीर भाटी (पी डब्लू 32) और इस मामले में मृतक और शिकायतकर्ता के भतीजे अनिल कुमार भाटी (पी डब्लू 39) मृतक और अपीलकर्ता के बीच एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में पूरी तरह से चुप हैं.37 वर्षीय नारायण यादव ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का उल्लेख किया है, लेकिन मात्र अपने दूसरे बयान (एक्स. का. 114) में सीआरपीसी यद्यपि खंड 161 के से दर्ज किया गया है । विचारण के दौरान नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) अपने बयान से पलट गए।इस प्रकार, अपनी गवाही में वह दोनों के बीच किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में चुप हैं।

(फ) अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने तीन सबूतों पर भरोसा है, अर्थात् (क) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के से नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) (एक्स. का. 114) का बयान, जिसमें उसने दावा विद्वान था कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों में खंड एक करण यादव ने उखंड बताया था कि सफेद मारुति कार, जो भागने वाली कार थी, अपीलकर्ता द्वारा उखंड दी गई थी, (ख) 15.07.1996 को, पाला @पाल सिंह @लक्कर @हरपाल सिंह ने पुलिस के समक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के से एक बयान (एक्स. का. 113) दिया था, जिसमें उसने दावा विद्वान था कि अपीलकर्ता करण यादव द्वारा अपराध करने के लिए इस्तेमाल की गई कार की आपूर्ति की गई थी, (सह-अभियोजन पक्ष) महेंद्र सिंह भाटी ने आरोप लगाया है कि अदालत को विश्वास है कि भाटी की हत्या के लिएयह अग्रेतर माना गया है कि मृतक महेंद्र सिंह भाटी ने सतबीर गुर्जर के गिरोह को संरक्षण दिया था, अपीलकर्ता ने महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह को संरक्षण दिया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 161 से दिए नारायण यादव (पी. डब्ल्यू.

37) के कथन (एक्स. का. 114) का अवलंब लेकर गलती की है क्योंकि नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गया।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत एक बयान कोई ठोस सबूत नहीं है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की धारा के तहत बयान का एक सीमित कार्य है, यानी केवल एक गवाह की विश्वसनीयता का खंडन करना या उसे बदनाम करना।इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के से कथित बयान (एक्स. का. 114) को साक्ष्य के एक मूल भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है.इस दलील को पुष्ट आदेश के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1959 एससी 1012] और वी. के. मिश्रा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य [एआईआर 2015 एससी 3043]** के मामलों पर भरोसा किया है। उसने अग्रेतर अभिवचन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड १६१ के से बयान का उपयोग अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है.इस दलील को पुष्ट आदेश के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **वीरेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य [एआईआर 2017 एससी 1228]** के मामले पर भरोसा किया है.इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड १६१ के तहत नारायण यादव (पी डब्लू ३७) द्वारा दिए बयान (एक्स. का ११४) के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में गलती की है ।

(h) वास्तव में, केस डायरी के अनुसार, नारायण यादव (पी डब्लू 37) के बयान सीबीआई द्वारा दो बार दर्ज किए गए थे।103) है।इस बयान में नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) ने कहीं भी न तो सफेद मारुति कार के बारे में उल्लेख किया है और न ही करण यादव द्वारा उनके सामने की गई किसी न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बारे में।यह मात्र अपने दूसरे बयान (एक्स. का. 114) में है, जो 16.08.1996 को दर्ज किया गया था, यानी लगभग दो साल पश्चात वह करण यादव द्वारा कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बारे में उल्लेख करता है, जिसमें उसे करण यादव द्वारा सूचित किया गया था कि डी. पी. यादव ने उसे एक बड़े काम के लिए कार दी थी।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत नारायण यादव (पी

डब्लू 37) द्वारा दिया पहला बयान (एक्स. का. 103) करण यादव की कथित न्यायेतर संस्वीकृति पर मौन है, और इसे केवल 16.08.1996 को दर्ज दूसरे बयान (उदा. का. 114) में पेश किया गया है, इसलिए, यह जांच एजेंसी द्वारा मनगढ़ंत कहानी है। अतः दूसरा वक्तव्य (उपर्युक्त के.का. 114), जो लगभग दो वर्षों के पश्चात दर्ज किया गया है, अत्यधिक संदिग्ध है।इसलिए, कथित बयान (एक्स. का. ११४) पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था.

(i)विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य को गलत पढ़ा है। इस तथ्य के बावजूद कि नारायण यादव (पी0 डब्लू0 37) ने अपने मुख्य परीक्षा में यह नहीं कहा कि पाला @ पाल सिंह, या करण यादव ने उसे बताया कि यह अपीलकर्ता है, जिसने निर्णय के पैराग्राफ 156 में विद्वान विचारण न्यायालय ने दावा किया कि नारायण यादव (पी डब्लू 37) ने अपनी गवाही में इस तथ्य का खुलासा कि पाला @पाल सिंह ने उसे बताया था कि अपीलकर्ता ने हमलावरों को कार दी थी.लेकिन वास्तव में नारायण यादव (पी डब्लू 37) ने अपनी परीक्षा में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

(जे) अभियोजन पक्ष ने मृतक महेंद्र सिंह भाटी से छुटकारा पाने के लिए एक आपराधिक साजिश में अपीलकर्ता की संलिप्तता को स्थापित आदेश और साबित आदेश के लिए एक सबूत के रूप में "**एक सफेद मारुति कार"**, भागने वाली कार का उपयोग किया है।यद्यपि अभियोजन पक्ष का मामला अपराध करने में एक सफेद मारुति कार के उपयोग के बारे में विरोधाभासों से भरा हैःवेदराम (पी डब्ल्यू 31), डी एन सिंघानिया (पी डब्ल्यू 33), ओम प्रकाश कयाल (पी डब्ल्यू 35) और अनिल कुमार भाटी (पी डब्ल्यू 39), शिकायतकर्ता, सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने एक सर्वव्यापी बयान दिया कि उन्होंने हमलावरों को एक कार में जाते देखा था।इन प्रत्यक्षदर्शियों में से किसी का भी दावा नहीं है कि हमलावर एक सफेद मारुति कार में निकले थे (ii) सुश्री मीनाक्षी सैनी (पीडब्लू 17) के अनुसार, कथित सफेद मारुति कार कुणाल कपूर के नाम पर पंजीकृत थी।फिर भी, अभियोजन पक्ष कुणाल कपूर से गवाह के रूप में पूछताछ करने में विफल रहा है।इसके अग्रेतर अभियोजन यह साबित करने में विफल

रहा है कि अपीलकर्ता ने कुणाल कपूर से कार खरीदी थी।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कार को कभी भी किसी ने भी देखा था

(k) साक्षी, या तो अपीलकर्ता के कब्जे में या सह-अभियुक्त करण यादव के कब्जे में.इसलिए, अभियोजन पक्ष अकेले कार को अपीलकर्ता से जोड़ने में विफल रहा है.इसी तरह, यह अपराध करने में कार के उपयोग को साबित करने में विफल रहा है।यहां तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के से दर्ज पाला उर्फ पाल सिंह का प्रकटीकरण बयान, जिसमें उसने दावा किया कि अपराध करने के लिए इस्तेमाल की गई कार उखंड अपीलकर्ता द्वारा दी गई थी, बयान का कथित हिस्सा अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है.इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध पाल सिंह के बयान के कथित हिस्से को पढ़ने में खुद को गलत तरीके से लगाया है.पुलुकुरी कोटैया बनाम किंग एम्परर [एआईआर 1947 पीसी 67] के मामले पर निर्भर करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी थी कि इस वस्तु के पिछले उपयोग या अतीत के इतिहास को सबूत के रूप में स्वीकार नहीं विद्वान जा सकता है।उन्होंने अग्रेतर असार मोहम्मद के मामले पर भरोसा किया है।उन्होंने आगे असर मोहम्मद अन्य बनाम यूपी राज्य। [AIR 2018 SC 5264] भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे के मामले पर भरोसा किया है और दायरे को समझाने के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे सलीम अख्तर @Mota बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले पर भरोसा किया है। [वायु 2003 SC 4076] अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए कि बयान का वह हिस्सा जो प्रकट करता है कि अपीलकर्ता द्वारा कार दी गई थी, अपीलकर्ता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैइसलिए, 15 की धारा 27 के अंतर्गत दिए विद्वान बयान के आधार पर, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को कार से जोड़ने में पूरी तरह से विफल रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ के से दिए विद्वान नारायण यादव के बयान (एक्स. का. ११४) के आधार पर विद्वत विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह गलत है।

अभियोजन पक्ष महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या के लिए कथित रूप से हमलावरों को किराए पर लेने के अपीलकर्ता के उद्देश्य को स्थापित करने में बुरी तरह से विफल रहा है।क्योंकि, अभियोजन पक्ष दोनों के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी, या हितों के टकराव या किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को अभिलेख पर लाने में विफल रहा है।वास्तव में, अभियोजन यह साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है कि मृतक और अपीलकर्ता कभी मिले थे.हालांकि, अभियोजन पक्ष ने एफ 0 आई 0 आर 0 और आपराधिक मामलों पर भरोसा किया है, जिसमें महेंद्र सिंह फौजी और सतबीर गुर्जर के गिरोह से जुड़े लोग शामिल थे, लेकिन सभी मामलों में, जहां अपीलकर्ता आरोपी था, उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर नहीं किया गया है।इसलिए, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को कार से जोड़ने में पूरी तरह से विफल रहा है

L) इसलिए, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को कार से जोड़ने में पूरी तरह से विफल रहा है, उन्होंने कहा कि प्राथमिकी को साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।इसलिए, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को कार से जोड़ने में पूरी तरह से विफल रहा है। वास्तव में, अनिल कुमार भाटी (पी डब्लू 39) प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों को दोहराता नहीं है. इसके अलावा, मृतक के पुत्र समीर भाटी (पी डब्लू 32) ने भी अपने पिता और अपीलकर्ता के बीच किसी दुश्मनी का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, जगदीश सिंह यादव (पी डब्लू 36), पहले आई ओ, ने भी मृतक और अपीलकर्ता के बीच किसी शत्रुता का उल्लेख नहीं किया है.इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि अपीलकर्ता का मृतक से छुटकारा पाने का एक मजबूत उद्देश्य है।

भले ही तर्क के लिए, यह स्वीकार किया गया था कि अपीलकर्ता के पास मृतक से छुटकारा पाने का एक उद्देश्य था, फिर भी उद्देश्य आवश्यक रूप से एक षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित नहीं करता है.इस दलील का समर्थन आदेश के लिए, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम पलटन महाल और अन्य [(2005) 3 एससीसी 169] के मामले पर भरोसा विद्वान था।उन्होंने अग्रेतर राज्य

बनाम नलिनी [(1999) 5 एससीसी 253] के मामले पर भरोसा किया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आदेश के अस्तित्व को कौन से साक्ष्य साबित करेंगे।

(m) **संपत कुमार बनाम के मामले पर भरोसा करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर, कृष्णागिरी [एआईआर 2012 एससी 1249],** विद्वान वरिष्ठ वकील ने दलील दी है कि, सबसे अच्छा मकसद अपीलकर्ता के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करता है।लेकिन संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता।इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार अभियोजन, अपीलकर्ता के विरुद्ध अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है। इस प्रकार, अपीलकर्ता बरी किए जाने का हकदार था।

(n) अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण गवाहों को निचली विचारण न्यायालय से रोक रखा है।इस तथ्य के बावजूद कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, धर्मवीर एक घायल चश्मदीद गवाह था, उससे विचारण के दौरान गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है.इसके अलावा, शिकायतकर्ता के अनुसार, बड़ी संख्या में चश्मदीद गवाह थे जिनके नाम उसने एफआईआर में दर्ज किए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभियोजन गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है।इसके आगे यहां तक कि धर्मवीर सिंह, जो कथित घटना के समय शिकायतकर्ता के साथ थे, उन्हें भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है.इसलिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

16. दूसरी ओर, सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता संदीप टंडन ने निम्नलिखित प्रतिवाद उठाए है:-

पहला, संबंधित समय के दौरान, क्षेत्र में दो गिरोह काम कर रहे थे, एक सतबीर गुर्जर से संबंधित था, और दूसरा महेंद्र सिंह फौजी से संबंधित था।मृतक ने पहले वाले गिरोह का संरक्षण किया, जबकि अपीलकर्ता ने बाद वाले गिरोह का पक्ष लिया।दोनों गैंग गैंग युद्ध की एक श्रृंखला में लगे हुए थे, क्योंकि वे दूसरे गैंग के सदस्यों को खत्म करना चाहते थे।क्षेत्र में गिरोह युद्ध का अस्तित्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक दूसरे के गिरोह के सदस्यों की हत्या के लिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज

किए गए थेःअपराध मामला संख्या 372/90 पुलिस स्टेशन लोनी 18 में दर्ज किया गया था. सतवीर, कालूराम राणा केसर गूजर, अशोक, अली, मैदान, मोहन, पप्पू नीरज, ओंकार सिंह, विक्रम, राणापाल, लोकेश व केंगा नाई के खिलाफ रशीद अली, साजन साह, मेहरदीन, अजमेठी, ब्रह्मा सिंह फेजू का हत्या का आरोप लगाया है। मृतक सलबीर गुर्जर के गिरोह से थे, जबकि आरोपी महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह से थे। इस मामले में छह लोग मारे गए थे, जिसमें राशिद अली भी शामिल था, जो वर्तमान मामले में सह-आरोपी औलाद अली का भाई था।

23-12-91 को, शोभा राम यादव और याहदा हसन की हत्या के लिए भरमपाल सिंह, प्रेमपाल, सतेंद्र, डाकपाल, अजीत और टीटू के विरुद्ध भा.दं.सं. की खंड 302 के से अपराध के लिए भोपा, मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी नंबर 251/91 बनाया गया था।इस मामले में भी आरोपी व्यक्ति महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह से थे, जबकि मृतक सतबीर गुर्जर के गिरोह से थे।

इसी तरह कवि नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 647/92 में प्रकाश पहलवान, प्रकाश गुजर, सत्यवीर गुजर, मान सिंह और सत्यपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।ये लोग सतबीर गुर्जर गैंग के थे।इसी तरह, डी पी यादव, महाराज सिंह, राम प्रधान, जितेंद्र, करण यादव और पाल सिंह के विरुद्ध बिसरख, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में अपराध मामला संख्या 38/93 दर्ज किया गया था।इस मामले में प्रकाश पहलवान, जयवीर, गुरमीत सिंह, राम प्रकाश, सतबीर गुर्जर के गिरोह के सदस्य 19 थे . वर्तमान मामले में डी. पी. यादव और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा घायल किया गया था।

इसके अलावा, भा.दं.सं. की धारा 307 के अपराध और वर्तमान मामले में सह-आरोपी पाल सिंह के विरुद्ध खंड 25,54 और 59 शस्त्र अधिनियम के अपराधों के लिए प्राथमिकी संख्या 134/96 पुलिस स्टेशन पाहेवा में दर्ज की गई थी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1990 से 1996 तक छह लंबे वर्षों तक सतबीर गुज्जर के गिरोह के सदस्यों और महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह के सदस्यों के बीच गिरोह युद्ध चल रहा था।जैसा कि पहले कहा गया है, मृतक और पहलवान सिंह ने पूर्व के

गिरोह का समर्थन किया, और अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने, वर्तमान मामले में, बाद के गिरोह का समर्थन किया। इसलिए, अपीलकर्ता के पास मृतक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करने का एक मजबूत उद्देश्य था।

इसके अग्रेतर अपराध संख्या 647/92 में उदयवीर सिंह (पीडब्लू 13) के अनुसार, डीपी यादव के बहनोई की मौत हो गई और डीपी यादव की बहन घायल हो गई।यह अपराध सतबीर गुर्जर के गिरोह के सदस्यों द्वारा किया गया था।इसलिए, मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ता का एक मजबूत उद्देश्य था। दूसरा, मृतक महेंद्र सिंह भाटी को खत्म करने के लिए, अपीलकर्ता ने इस मामले में एक सफेद मारुति कार खरीदी थी । यह कार अपीलकर्ता द्वारा अन्य सह-आरोपी, करण यादव को दी गई थी.इस सफेद मारुति कार का उपयोग दो हमलावरों ने अपराध स्थल से भागने के लिए किया था।तथ्य यह है कि कार अपीलकर्ता द्वारा दी गई थी. नारायण यादव (अ. डब्लू. 37) के बयान (एक्स. का. 114) और पुलिस को दिए गए पाल सिंह के खुलासे के बयान (एक्स. का. 113) से स्पष्ट है। ."धारा 161 सी. आर. पी. सी. (एक्स. के. 114) के अंतर्गत दिए गए अपने पूरक बयान में, नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) ने कहा है कि करण यादव ने उसे बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार डी. पी. यादव द्वारा उसे" "एक बड़े काम" "के लिए दी गई थी।"

इसके अग्रेतर एक सह-अभियुक्त पाला @पाल सिंह ने अपने बयान में, (एक्स. का. 113) खुलासा किया कि सफेद मारुति कार उसे अपीलकर्ता द्वारा दी गई थी.इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता न मात्र हत्या का मास्टरमाइंड था, बल्कि वही था जिसने हमलावरों को भागने वाली कार भी दी थी।इसलिए, अभियोजन महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करने के लिए एक आपराधिक साजिश के अस्तित्व को साबित करने में सफल रहा है।इस प्रकार, कथित जघन्य अपराध में उसकी संलिप्तता अभियोजन द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है.

17. प्रत्युत्तर में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह प्रस्तुत करते हैं कि गिरोह युद्ध का सिद्धांत न मात्र एक मनगढ़ंत कहानी है, बल्कि तथ्यों द्वारा भी झूठा है।

क्योंकि, प्रथम सूचना संख्या 372 / 1990 में, अपीलकर्ता तो अभियुक्त भी नहीं है । इसलिए, अपीलकर्ता उक्त मामले में किए गए कथित अपराध से जुड़ा नहीं है।

यहां तक कि प्रथम सूचना संख्या : 251/1991 के तथ्यों को भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलत पढ़ा है। उस मामले में आरोपी का नाम ब्रह्म पाल सिंह है, न कि धरम पाल सिंह।इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष को कि "धरम पाल सिंह कथित मामले में एक अभियुक्त है" अभिलेख द्वारा ही गलत साबित किया है।

इसी तरह, अपराध संख्या 647/1992 में फिर से, अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसलिए उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि प्रथम सूचना संख्या 38/1993 में, हालांकि अपीलकर्ता का नाम लिया गया था, उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता फिर से इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। यहां तक कि प्रथम सूचना संख्या 134/1996 में, जहां पाला उपनाम पाल सिंह एक आरोपी था, उसे भी उक्त मामले में बरी कर दिया गया है। अपीलकर्ता का उक्त मामले से कोई संबंध नहीं है।

इसलिए, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह से जुड़ा हुआ है। इसलिए, गैंग वॉर की कहानी अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है।

18. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया और मामले के अभिलेख की जांच की।

19. शिकायतकर्ता अनिल भाटी (पी. डब्ल्यू. 39), मृतक के भतीजे ने विचारण न्यायालय को सूचित किया कि 13.09.1992 को वह महेन्द्र सिंह भाटी के घर पर था।महेंद्र सिंह के बेटे ने उन्हें सूचित किया कि सीआईडी इंस्पेक्टर का एक टेलीफोन कॉल आया है, जो चाहते हैं कि वह गांव भंगल जाएं।इसलिए महेंद्र सिंह भाटी अपनी

कार में चले गए।रास्ते में कार रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी।उनके अनुसार, भाटी के घर से बाहर निकलने के तुरंत पश्चात उन्होंने उनका मोटरसाइकिल पर भी पीछा किया।उसने रेलवे क्रॉसिंग गेट पर मोटरसाइकिल भी रोक दी।उनके अनुसार, मात्र दो लोगों ने महेंद्र सिंह भाटी की कार पर गोली चलाई।इनमें से एक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी और उसकी लंबाई 6 फुट थी, जबकि दूसरे की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी, लेकिन वह छोटा आदमी था, जिसकी लंबाई 5 से 5 फुट 5 इंच थी।ये दोनों एक कार में बैठ गए और दादरी की ओर चले गए।उसके अनुसार, घटना के पश्चात वह पुलिस स्टेशन दादरी गया।उन्होंने पूरी कहानी नरेन्द्र भाटी (पी. डब्ल्यू. 10) को लिखवाई और उनके माध्यम द्वारा शिकायत (एक्स. का. 30) लिखवाई।इसके बाद उन्होंने इसे पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।अपनी मुख्य -परीक्षा में, वह स्वीकार करता है कि उसे हमलावरों का स्मरण नहीं है क्योंकि यह बहुत लंबा समय हो गया है।

20. मुख्य - परीक्षा में उसका सामना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 से अभिलिखित किए गए उसके कथन से होता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 से अभिलिखित किए गए उसके कथन थे उसने दावा किया किया था कि श्री भाटी पर सात से आठ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था, जबकि उनके प्रमुख परीक्षण ने दावा किया कि मात्र दो व्यक्तियों ने श्री भाटी पर हमला किया था।इसके अलावा, उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि यह पहली बार है कि उसने दो हमलावरों की उम्र और ऊंचाई का खुलासा किया है।

21. दिलचस्प बात यह है कि इस गवाह ने अपनी शिकायत में जो कहा था, उससे अपना रुख बदलकर अदालत में जो कहा है, वही दिया है।प्राथमिकी में उसने दावा किया है कि सात से आठ लोगों ने श्री भाटी पर हमला किया था।लेकिन अपने परीक्षण में, वह दावा करता है कि मात्र दो व्यक्तियों ने श्री भाटी पर हमला किया था।सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राथमिकी और अपनी जांच में उसने दावा किया कि दोनों व्यक्ति एक कार में अपराध स्थल से भाग गए थे।उन्होंने न तो कार के निर्माण, न कार के रंग और न ही कार के पंजीकरण नंबर का वर्णन किया।इसके अलावा, अपनी शिकायत में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अपने बयान में, उन्होंने

दावा किया कि हमलावरों ने चिल्लाया था कि अब प्रकाश पहलवान को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास करें।इस प्रकार, उसने कथित हत्या का कारण बताया था। फिर भी, अपनी गवाही में, वह उद्देश्य के बारे में चुप रहता है।यह एक चूक है जो विरोधाभास की कोटि में आती है।लेकिन यह तथ्य कि वह हमलावरों की संख्या सात से आठ से बदलकर मात्र दो कर देता है, यह तथ्य कि अपराध के समय हमलावरों ने क्या कहा होगा, इस बारे में वह मौन है, उनकी गवाही की सत्यता पर संदेह की छाया डालता है। यह भी संदेह पैदा करता है कि शिकायत वास्तव में एक चश्मदीद गवाह है या नहीं?क्योंकि, अपनी गवाही में, वह स्वीकार करता है कि उसे स्मरण नहीं है कि हमलावर दादरी, या सूरजपुर की ओर भाग गए थे।दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह गवाह हमलावरों के लिए एक अजनबी होने का दावा करता है, अभियुक्त व्यक्तियों को कभी भी परीक्षण पहचान परेड का सामना नहीं करना पड़ा है।वास्तव में, शिकायतकर्ता अदालत में भी हमलावरों को पहचानने में विफल रहता है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गवाह कथित अपराध में अपीलकर्ता की भागीदारी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहता है। इस प्रकार, यह गवाह अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने में अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करता है।

22. समीर भाटी (पी डब्ल्यू 32) मृतक का पुत्र है।उसने अपने प्रमुख परीक्षा में कहा कि महेंद्र सिंह भाटी उनके पिता थे।उनकी 13.09.1992 को हत्या कर दी गई।उनकी मृत्यु के समय उनके पिता दादरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे।उन्होंने अग्रेतर दावा किया कि 13 सितंबर 1992 को रोहिलापुर गांव के प्रधान अजीत सिंह तोमर ने अपने पिता से टेलीफोन पर बात की।उसने अपने पिता को सूचित किया कि सीबी-सीआईडी इंस्पेक्टर उससे बात करना चाहता है।इसलिए उनके पिता भंगेली गांव चले गए।उसके अनुसार, उसके पिता अपने ड्राइवर और बंदूकधारी के साथ अपनी कार में चले गए। लेकिन वो खुद अस्वस्थ थे तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए।उसकी बहन ने उसे इस तथ्य के बारे में बताया कि उनके पिता दादरी में मारे गए हैं रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग, जब वह डॉक्टर के पास थे।वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके पिता और उदय प्रकाश आर्य पीछे की सीट पर पड़े हुए हैं।उन्होंने यह भी देखा कि उनके पिता का बंदूकधारी घायल हो गया और कार के बाहर पड़ा था।इसलिए श्री भाटी, उदय

प्रकाश आर्य और घायल बंदूकधारी को तुरंत भगवती नर्सिंग होम ले जाया गया।उन्होंने अग्रेतर दावा किया कि उनके पिता को कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, जिनके विरुद्ध उनके पिता ने पुलिस को लिखा था।

23. दिलचस्प बात यह है कि यह गवाह भी, जो मृतक का बेटा है, मृतक, उसके पिता और अपीलकर्ता के बीच किसी शत्रुता, या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करता है।यहां तक कि जब वह दावा करता है कि उसके पिता को कुछ व्यक्तियों द्वारा धमकी दी गई थी, तब भी वह अपीलकर्ता का उल्लेख नहीं करता है।

24. चश्मदीद गवाहों, अर्थात् राज कुमार (पी डब्लू 7), हेड कांस्टेबल वेदराम कौशिक (पी डब्लू 31), डी एन सिंघानिया (पी डब्लू 33), ओम प्रकाश कयाल (पी डब्लू 35) और अनिल भाटी (पी डब्लू 39) ने कथित अपराध में अपीलकर्ता की भागीदारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए इस न्यायालय को उनके बयानों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।इसके अलावा, चूंकि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि महेंद्र सिंह भाटी की मृत्यु एक हत्या के रूप में हुई थी, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है।मुख्य मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष यह है कि क्या अपीलकर्ता महेंद्र सिंह भाटी की कथित हत्या में शामिल था या नहीं?

25. अभियोजन ने अपीलकर्ता और मृतक के बीच शत्रुता के तीन कारण दिए हैंःसबसे पहले, दोनों अपीलकर्ता और मृतक ने दो अलग-अलग और युद्धरत गिरोहों को संरक्षण दिया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।दूसरा, दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, दोनों अलग-अलग राजनीतिक दलों के मौजूदा विधायक थे।तीसरा, सतबीर गुर्जर के गिरोह के सदस्यों ने अपीलार्थी के बहनोई की हत्या कर दी थी और उसकी बहन को घायल कर दिया था, जिसके लिए केस संख्या 647/92 दर्ज किया गया था.

26. दोनों गिरोहों के बीच गिरोह युद्ध को साबित आदेश के लिए अभियोजन पक्ष ने उदयवीर सिंह (पी. डब्ल्यू. 13) को पेश किया है।उन्होंने कहा कि 1982 से 1995 के बीच वह मेरठ में सीबीआई में इंस्पेक्टर थे।उन्होंने आघे कहा कि अपराध संख्या 372/1990 में छह व्यक्तियों अर्थात् शाकिर अली, साजन शाह, मेहर सीन,

अजमेरी, ब्रह्म सिंह और फैजू की मृत्यु से संबंधित थी।उनके अनुसार आरोपियों के नाम सतवीर, कालू राम राणा, मेहर गुज्जर, अशोक, अनिल, मदन मोहन उर्फ पप्पू, नीरज, ओंकार सिंह, विक्राय रणपाल, लोकेश और बेंगा नाई हैं। उनके अनुसार, इन सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। यद्यपि इस मामले में, अपीलकर्ता को कभी भी आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था । इसलिए, यह मामला पूरी तरह से अपीलकर्ता से संबंधित नहीं है।

27. इस गवाह ने अपराध संख्या 647/1992 के बारे में भी बताया है, जो पुलिस स्टेशन कवि नगर में दर्ज किया गया था।इस गवाह के अनुसार, इस मामले में, कमल राम यादव की हत्या कर दी गई थी, और उसकी पत्नी, श्रीमती सत्यवती, जो अपीलकर्ता की बहन है, घायल हो गई थी.इस मामले में प्रकाश पहलवान, प्रकाश गुर्जर, सत्यवीर गुर्जर, मान सिंह और सत्यपाल आरोपी थे।इन सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया था।यद्यपि निश्चित रूप से, वर्तमान मामले में मृतक के मारे जाने के पश्चात यह अपराध दर्ज किया गया था। इसलिए, यह मामला भी मृतक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के लिए किसी भी उद्देश्य का आधार नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले पर आदेश दिया है ताकि इस तथ्य पर आदेश दिया जा सके कि इस मामले में, अपीलार्थी की बहन सत्यवती घायल हो गई थी.इसके अलावा, इस मामले में आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर सतबीर गुर्जर के गिरोह से संबंधित थे। यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि यह मामला महेंद्र सिंह भाटी की कथित हत्या के पश्चात दर्ज किया गया था।इसलिए, अपीलार्थी की बहन को हुई चोट मृतक, महेंद्र सिंह भाटी की हत्या का आधार नहीं बन सकती है.

28. इसी प्रकार, मनोज कुमार कौशिक (पी. डब्ल्यू. 12) की एफ. आई. आर. संख्या 251/1991 के बारे में गवाही देने के लिए जांच की गई है, जो पुलिस स्टेशन भोपा, मुजफ्फरनगर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।उनके अनुसारइस मामले में शोभा राम यादव और शहदा हसन की हत्या कर दी गई थी।इस मामले में आरोपी ब्रह्मपाल सिंह, डॉक्टर प्रेमपाल, सहेंद्र, जयपाल, अजीत और टीटू थे।उन्होंने बताया कि आरोपी महेंद्र फौजी गैंग के सदस्य हैं।इसके अलावा, जांच के दौरान, यह पता चला कि शोभा राम

यादव सतबीर गुर्जर के गिरोह से संबंधित थी।इस गवाह के अनुसार, सतबीर गुर्जर के गिरोह और महेंद्र फौजी के गिरोह के बीच प्रतिद्वंद्विता है।

29. यद्यपि इस गवाह की गवाही भी अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में कथित अपराध से नहीं जोड़ती है।क्योंकि, इस गवाह ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता का महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह से कोई संबंध है.इसके अलावा, प्राथमिकी नंबर 251/1991 में कहीं भी अपीलकर्ता का नाम नहीं दिया गया है।"इसके बजाय, यह" "ब्रह्म पाल सिंह" "का नाम है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से" "धरम पाल सिंह" "के रूप में पढ़ा है।"इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आसानी से उपलब्ध साक्ष्य को गलत पढ़ा है.इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा है कि यह प्राथमिकी भी अपीलकर्ता से संबंधित नहीं है.

30. अंत में, मामचंद, इंस्पेक्टर (पी. डब्ल्यू. 27) की एफ. आई. आर. संख्या 134/1996 के बारे में गवाही देने के लिए अभियोजन द्वारा जांच की गई है, जो वर्तमान मामले में उपनाम पाला सिंह के विरुद्ध पुलिस स्टेशन-पेहवा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।अपनी प्रमुख - परीक्षा में उन्होंने कहा है कि 18.06.1996 को उन्हें एसएचओ, पुलिस स्टेशन पेहवा के रूप में तैनात किया गया था।उसी दिन उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पाला सिंह और जयपाल सिंह गांव-पहवा में जस्सा सिंह के घर के बाहर सो रहे हैं।उन्होंने अग्रेतर दावा किया कि पुलिस ने उक्त घर की घेराबंदी करने के पश्चात पाला सिंह के पास से एक एके-47 बरामद की।उन्होंने अग्रेतर दावा किया कि प्राथमिकी संख्या 134/1996, पाला सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई थी.यद्यपि यह प्राथमिकी भी अपीलकर्ता से जुड़ी नहीं है। क्योंकि, अपीलकर्ता इस मामले में अभियुक्त नहीं है।

31. इन तथ्यों पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने एक गैंग वार की कहानी गढ़ने की कोशिश की है और अपीलकर्ता को महेंद्र सिंह फौजी के गैंग का समर्थन करने के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।किसी भी पुलिस गवाह के लिए, मनोज

कुमार कौशिक (पीडब्ल्यू12), या उदयवीर सिंह (पीडब्ल्यू13), ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि अपीलकर्ता महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह का समर्थन कर रहा है।मनोज कुमार कौशिक (पी. डब्ल्यू. 12) ने मात्र यह कहा है कि सतबीर गुर्जर के गिरोह और महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह के बीच बहुत बड़ी प्रतिद्वंद्विता है।इसलिए, महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह के साथ अपीलकर्ता को जोड़ने के लिए साक्ष्यों का अभाव है। इसके अलावा, न तो समीर भाटी (पी0 डब्लू0 32), मृतक का बेटा और न ही अनिल भाटी (पी0 डब्लू0 39), शिकायतकर्ता, यह दावा करता है कि दोनों मृतक और अपीलकर्ता राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी।

32. यदि कोई प्रतिद्वंद्विता या शत्रुता थी, तो निश्चित रूप से, मृतक के बेटे समीर भाटी (पी. डब्ल्यू. 32) ने इस तथ्य के बारे में बयान दिया होगा। इस पहलू पर उसकी चुप्पी इस तथ्य के बारे में बहुत कुछ बताती है कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। इसके अलावा, हालांकि समीर भाटी (पी. डब्ल्यू. 32) अपनी गवाही में दावा करते हैं कि उनके पिता को कुछ लोगों द्वारा धमकी दी गई थी, फिर भी उन्होंने अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया।इसके अलावा, वह कहीं भी यह नहीं कहता है कि उसके पिता को महेंद्र सिंह फौजी के गिरोह के सदस्यों द्वारा धमकी दी जा रही है।इसलिए, ये सभी सबूत, भले ही वे एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के पश्चात पहली नजर में प्रभावशाली प्रतीत हों।इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय कानूनी रूप से यह निष्कर्ष निकालना अनुचित है कि अपीलकर्ता का मृतक, महेंद्र सिंह भाटी से छुटकारा पाने का कोई उद्देश्य था।

33. नारायण यादव (पी डब्ल्यू 37) शिव फार्म हाउस के मालिक हैं।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के से सीबीआई ने दो बार उनका बयान दर्ज कियाःपहला 26.08.1994 को और दूसरा 16.08.1996 को।इस प्रकार, लगभग दो वर्षों का एक लंबा अंतराल है।अभियोजन पक्ष द्वारा नारायण यादव (पी डब्लू 37) की जांच इस तथ्य को स्थापित आदेश के लिए की गई कि अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, करण यादव, पाला उपनाम पाल सिंह, जयपाल गुर्जर और महाराज सिंह के बीच एक अंतरंग संबंध है। यद्यपि यह गवाह विचारण के दौरान मुकर गया ।फिर भी,

अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के क्रम विद्वान निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 अंतर्गत नारायण यादव (पी डब्लू 37) द्वारा दिनांक 16.08.1996 दिए गए दूसरे बयान (Ex. Ka. 114) को पढ़ा है।

34. विद्वा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए विद्वान नारायण यादव (पी डब्लू 37) के बयान (एक्स. का. 114) के उपयोग को जोरदार चुनौती दी है।इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए बयान का उपयोग किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए किया जा सकता है या नहीं?

35. तहसीलदार सिंह और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में दिए गए कथन की व्याप्ति, परिधि और उपयोग पर विस्तार से चर्चा की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले थेः-

उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं(1) अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी साक्षी द्वारा लिखित रूप में दिए गए कथन का उपयोग मात्र साक्षी के कथन का खंडन करने के लिए किया जा सकता है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है।(i) जब कथन में पाए जाने वाले सस्वर पाठ या सस्वर पाठ में आवश्यक रूप से निहित हो; चित्रण: पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए बयान में गवाह ने कहा कि वह एक विशेष समय पर बी को छुरा घोंपते हुए देखा, लेकिन गवाह-बॉक्स में वह कहता है कि उसने ए और सी को एक ही समय में बी को छुरा मारते हुए देखा; पुलिस के सामने बयान में "केवल" शब्द निहित हो सकता है, यानी गवाह ने ए को केवल बी को छुरा मारते हुए देखा; (ii) एक बयान में एक सकारात्मक सस्वर पाठ का एक नकारात्मक पहलू; चित्रण:पुलिस के सामने दर्ज बयान में गवाह कहता है कि एक काले आदमी ने बी को चाकू मारा, लेकिन गवाह-बॉक्स में वह कहता है कि एक गोरे आदमी ने बी को चाकू मारा; पहले के बयान में यह समझा जाना चाहिए कि न केवल अपराधी एक काले रंग का आदमी था, बल्कि

यह भी कि वह गोरा रंग का नहीं था; और iii) जब पुलिस के सामने दिया गया बयान और अदालत के सामने दिया गया बयान एक साथ नहीं हो सकता है; चित्रण:गवाह ने पुलिस के सामने दर्ज बयान में कहा कि 'ए' बी चाकू मारने के बाद उत्तरी लेन से भाग गया, लेकिन अदालत में वह कहता है कि छुरा मारने के तुरंत बाद वह दक्षिणी लेन की तरफ भाग गया; क्योंकि वह छुरा घोंपने के तुरंत बाद भाग नहीं सकता था, यानी एक ही समय में, उत्तरी लेन के साथ-साथ दक्षिणी लेन की ओर, यदि एक कथन सत्य है, तो दूसरा आवश्यक रूप से गलत होना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कथित बयान का उपयोग केवल गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

वी. के. मिश्रा और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के बीच अंतर्संबंध पर निम्नलिखित रूप में विस्तार खंड चर्चा की हैः-

"14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, जिसका शीर्षक "पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा" शीर्षक वाले पीसी में किसी भी जांच अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा का प्रावधान है, जब ऐसे व्यक्ति को तथ्यों के मामलों और परिस्थितियाँ से परिचित होना चाहिए ।
धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए पुलिस बयान का उद्देश्य और तरीका किसी भी मुकदमे में इस्तेमाल किया जा सकता है:

दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 162 में उपदर्शित खंड 162 दंड प्रक्रिया संहिता निम्नानुसार हैः

162 पुलिस को दिए गए कथनों पर हस्ताक्षर न किया जाना-साक्ष्य में कथनों का उपयोग- (1) इस अध्याय से अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान पर यदि उसे लिखित रूप में घटा दिया जाता है तो उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे और न ही ऐसे किसी कथन या उसके किसी अभिलेख का, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे कथन या अभिलेख के किसी भाग का उपयोग किसी प्रयोजन के लिए किया

जाएगा, इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, उस समय जब ऐसा कथन किया गया हो, अन्वेषण से किसी अपराध के संबंध में किसी जांच या विचारण में किया जाएगाः बशर्ते कि इस तरह की जांच या मुकदमे में अभियोजन के लिए किसी गवाह को बुलाया जाता है, जिसके बयान को लिखित रूप में पूर्वोक्त रूप में कम कर दिया गया है, तो उसके बयान के किसी भी हिस्खंड का, यदि विधिवत रूप खंड साबित हो गया है, तो आरोपी द्वारा और अभियोजन द्वारा विचारण की अनुमति खंड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा प्रदान की गई तरीके खंड ऐखंड गवाह का खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और जब ऐखंड बयान के किसी भी हिस्खंड का इस तरह उपयोग किया जाता है, तो ऐखंड गवाह की पुनर्परीक्षा में भी उसके किसी भी हिस्खंड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मात्र उसकी प्रतिपरीक्षा में संदर्भित किसी भी मामले को स्पष्ट करने के उद्देश्य खंड।

2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करने वाले किसी भी बयान पर इस अधिनियम की धारा में कुछ भी लागू नहीं समझा जाएगा।

व्याख्या.स्पष्टीकरण.- उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक विरोधाभास की राशि हो सकती है यदि वह महत्वपूर्ण और अन्यथा प्रासंगिक प्रतीत होता है, इस संदर्भ में कि ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक एक विशेष संदर्भ में एक विरोधाभास की मात्रा तथ्य का प्रश्न होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 ऐखंड गवाहों के विरोधाभास के सीमित प्रयोजन को छोड़कर, जो वहां इंगित किए गए हैं, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान का उपयोग करने खंड रोकती है।एक गवाह द्वारा पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161(1) के तहत दिया गया बयान का इस्तेमाल केवल ऐसे गवाह के खंडन के उद्देश्य से किया जा सकता है जो उसने विचारण में कहा है जैसा कि परंतुक में दिया गया है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के अंतर्गत जाँच के दौरान अभिलिखित किए गए कथन, जांच के दौरान ठोस सबूत के टुकड़े नहीं हैं लेकिन मुख्य रूप से

सीमित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है :- (i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत एक अभियुक्त द्वारा ऐसे गवाह का खंडन करना ; (ii) अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे गवाह का विरोधाभास भी लेकिन न्यायालय की अनुमति से और (iii) यदि आवश्यक हो तो गवाह की फिर से परीक्षा।

16. न्यायालय स्वप्रेरणा से पुलिस को दिए गए बिना साबित किए गए बयानों का उपयोग नहीं कर सकता है और उनके संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछ सकता है जो न्यायालय में साक्षी की गवाही से असंगत है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार "यदि विधिवत साबित हो" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गवाहों के बयान के रिकॉर्ड को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से और न ही जांच की जा सकती है, लेकिन उन्हें प्रति-परीक्षा के दौरान जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी साक्षी खंड स्वीकृति प्राप्त करके विरोधाभास के उद्देश्य के अभिलेख विधिवत साबित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी के समक्ष बयान का उपयोग विरोधाभास के लिए मात्र किया जा सकता , लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के सख्त अनुपालन के पश्चात ही इसका उपयोग किया जा सकता है ।

17. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 निम्नानुसार हैः

145. लिखित पूर्व कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षाकिसी गवाह से लिखित रूप में उसके द्वारा दिए गए पिछले बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है या लिखित रूप में कम किया जा सकता है, और प्रश्नगत मामलों के लिए प्रासंगिक है, इस तरह का लेखन उसे दिखाए बिना, या साबित किए बिना, लेकिन, यदि लेखन द्वारा उसका खंडन करने का इरादा है, तो लेखन को साबित करने से पहले, उसके ध्यान को इसके उन हिस्सों की ओर बुलाया जाना चाहिए जिनका उपयोग उसके खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है।

18 साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 से अधीन जब इसका आशय लिखित रूप में अपने पिछले कथन द्वारा साक्षी का खंडन करना है तो ऐखंड साक्षी का ध्यान उससे उन भागों की ओर अवश्य ही आकृष्ट किया जाना चाहिए जिनका उपयोग लेखन का उपयोग करने खंड पूर्व उससे खंडन करने से प्रयोजन से लिए किया जाना है।किसी

साक्षी का बयान अभिलिखित करते समय विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुलिस कथन का वह भाग, जिसके साथ वह साक्षी का खंडन करने का आशय रखता है, उसकी प्रति परीक्षा में साक्षी के ध्यान में लाया जाए।साक्षी का ध्यान उस भाग की ओर आकर्षित किया जाता है और इसमें प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसे दोहराते हुए।यदि साक्षी उस भाग को स्वीकार करता है जिसका उसका विरोध करने का इरादा था, तो यह साबित हो जाता है और अग्रेतर विरोधाभास के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है और इसे साक्ष्य की सराहना करते हुए पढ़ा जाएगा।यदि वह कथन का वह भाग किए जाने से इंकार करता है, तो उसका ध्यान उस कथन की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और अभिसाक्ष्य में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।इस प्रक्रिया से विरोधाभास को मात्र अभिलेख पर लाया जाता है, लेकिन इसे अभी तक साबित नहीं किया जा सका है।इसके पश्चात् जब जाँच अधिकारी की न्यायालय में परीक्षा की जाती है तो उसका ध्यान अंतर्विरोध के प्रयोजन के लिए अंकित परिच्छेद की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, तब यह जाँच अधिकारी के अभिसाक्ष्य में साबित किया जाएगा जो पुनः पुलिस कथन का उल्लेख करके साक्षी के कथन के बारे में साक्ष्य देगा।इस प्रक्रिया में फिर से पुलिस के बयान का उल्लेख करना और उस हिस्से को चुनना शामिल है जिसके साथ बयान के निर्माता का इरादा विरोधाभासी था।यदि साक्षी का कथन के उस भाग से सामना नहीं हुआ था जिसके साथ बचाव पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुपालन में साबित नहीं हुए बयानों का स्वतः उपयोग नहीं कर सकता है, अर्थात् विरोधाभास के लिए इच्छित भागों पर ध्यान आकर्षित करके।

37. इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 161 से दिए गए कथन को अत्यधिक सीमित प्रयोजन के लिए उपयोग आदेश की अनुमति देती है, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 162 (1) के परंतुक के साथ पठित साक्ष्य

अधिनियम की खंड 145 के अनुसार, अर्थात् जाँच के दौरान उसने जो कहा है उस पर बयान देने वाले का खंडन करने के लिए । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 मैं दिए गए कथन का उपयोग किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।

38. वास्तव में, वीरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर यह राय व्यक्त की है कि " पीडब्लू-12 को अभियोजन द्वारा बदनाम किया गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के सी0 आर 0 पी0 सी0 की धारा 161 मैं दर्ज किए गए उसके पिछले बयानों के संदर्भ में उसका खंडन किया गया है, पीडब्लू-12 की गवाही का कोई हिस्सा अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषी का निर्धारण करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। अपने जाँच के दौरान उसके द्वारा दिए गए बयान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान, साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं, जिन पर अदालत द्वारा किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया जा सके।"(जोर दिया गया है)

39. विद्वान न्यायाधीश ने भगवान दास बनाम दिल्ली राज्य [(2011) 6 एस. सी. सी. 396] के मामले पर भरोसा किया है ताकि इस सिद्धान्त को स्पष्ट किया जा सके कि, क्योंकि गवाह आदेश के दौरान मुकर गया था, और उक्त गवाह ने बयान धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज उसके बयान खंड किया था, जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।इसलिए, एक अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, उक्त निर्णय से इस सिद्धांत को निकालने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय दूसरे कथन को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा है (एक्स. का. 114)

नारायण यादव (P.W. 37) धारा 161 सी0 आर 0 पी0 सी0 के तहत दिया गया। हालांकि, ऐसा करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने तीन गलतियां की हैं: प्रथमतः, इसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के परंतुक की उपेक्षा की है जो स्पष्ट रूप खंड उस सीमित प्रयोजन को विहित करती है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

161 से अभिलिखित कथन का उपयोग किया जा सकता है।दूसरा, इसने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है, जिनमें से कुछ मामलों का ऊपर उल्लेख किया गया है।तीसरा, इसने पूर्ववर्ती नियमों की अनदेखी की है।

उदाहरण के नियम कानून के विकास में निरंतरता और निश्चितता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कानून की व्याख्या और विकास में सामंजस्य होना चाहिए।यदि पूर्वोदाहरण के नियमों की अनदेखी की जाती है तो यह अनावश्यक रूप से विधि में विसंगति का कारण बनेगा।इस प्रकार, न्यायिक अनुशासन मिसाल के उस नियम की मांग और निर्देश देता है कि आत्मा और पत्र दोनों में पालन किया जाना चाहिए । [शाह फैसल बनाम भारत संघ, (2020) 4 एससीसी 1]

भगवान दास (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय को तहसीलदार सिंह (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए था। बाद का निर्णय मात्र सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए बयान के दायरे और उपयोग से पहले लिया गया निर्णय था, बल्कि यह एक संविधान पीठ का भी निर्णय था।

इस प्रकार उक्त निर्णय विद्वान खंडपीठ के लिए बाध्यकारी था जिसने भगवान दास (उपरोक्त) के मामले का निर्णय किया। इसके अलावा, जबकि भगवान दास (सुप्रा) का मामला एक विद्वान खंडपीठ द्वारा तय किया गया था, वी. के. मिश्रा (उपरोक्त) का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक विद्वान पूर्ण पीठ द्वारा तय किया गया था। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय को तहसीलदार सिंह (ऊपर) के मामले में विद्वान संविधान पीठ द्वारा और वी. के. मिश्रा और अन्य (ऊपर) के मामले में विद्वान पूर्ण पीठ द्वारा घोषित विधि के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए था।

इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए नारायण यादव (पी डब्लू 37) द्वारा दिए दूसरे बयान (एक्स. का. 114) का उपयोग करते हुए कानून को गलत तरीके से लागू किया है। अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपयोग किए साक्ष्य का तीसरा टुकड़ा पाला

@पाल सिंह @लक्कड़ उपनाम हरपाल सिंह द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन (एक्स. का. 113) है।उनका वक्तव्य (एक्स. का. 113) इस प्रकार हैः- -

मुझे, जयपाल गुर्जर और महाराज सिंह को जून 1992 में बुलंदशहर के विधायक डी. पी. यादव और उनके रिश्तेदार करण यादव ने सफेद मारुति कार दी थी।हत्या आदेश के लिए इस कार का उपयोग आदेश के लिए, मैंने हत्या से पहले गुड़गांव के मारुति कार सर्विस स्टेशन पर इस कार की सर्विसिंग कराई थी और मैंने इस कार को हरपाल सिंह के नाम पर सर्विसिंग कराई थी।सितंबर 1992 के पहले सप्ताह में इस कार की सर्विसिंग की गई थी।मैं आपको गुड़गांव ले जा सकता हूं और अदालत के पास सर्विस स्टेशन की पहचान कर सकता हूं। उक्त प्रकटीकरण कथन (एक्स. का. 113) पाल सिंह द्वारा 15.07.1996 को दिया गया था।

41. विद्वान विचारण न्यायालय ने कथित प्रकटीकरण कथन (एक्स. का. 113) पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसा किया है कि सफेद मारुति कार, जिसका उपयोग भागने वाली कार के रूप में किया था, अपीलकर्ता द्वारा कथित हमलावरों को दी गई थी.इसलिए, अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी.इसलिए, अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ सपठित धारा 302 के से अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

42. यद्यपि इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या पाला सिंह द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान (एक्स. का. 113) कि कार अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई थी और इसका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था, को अपीलकर्ता के विरुद्ध पढ़ा जा सकता है या नहीं?

43. वास्तव में, यह कहना कठिन है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 27 पुलिस के समक्ष किसी अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन से संबंधित है।जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में कहा गया है कि "एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति एक आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि न्यायालय को स्वीकारोक्ति किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण हुई प्रतीत होती है, जैसा कि

संदर्भ में है आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप, एक व्यक्ति से आगे बढ़ना अधिकार में और पर्याप्त, न्यायालय की राय में, देने के लिए (ख) अभियुक्त व्यक्ति ऐसा आधार प्रदान करता है, जो उसे यह सोचने के लिए उचित प्रतीत होगा कि इसे बनाने से उसे अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के संदर्भ में कोई लाभ होगा या सांसारिक प्रकृति की किसी बुराई से बचा जा सकेगा। " "

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कथित आरोपी के विरुद्ध पुलिस के समक्ष आरोपी द्वारा दिए गए किसी भी बयान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत एक बयान के उपयोग की अनुमति देती है, बशर्ते कि यह एक मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो, भले ही आरोपी इस समय पुलिस हिरासत में हो।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 निम्नानुसार हैः- -

27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी कितनी साबित की जा सकती है।परन्तु जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि उसका पता चला है तो ऐसी जानकारी की उतनी मात्रा, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती है या नहीं, जो स्पष्ट रूप से इस प्रकार खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साबित की जा सकती है।

44. पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य (पूर्वोक्त) के प्रसिद्ध मामले में, माननीय प्रिवी काउंसिल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की व्याप्ति और परिधि के बारे में विस्तार खंड चर्चा की थी-

9. धारा 27, जो कलात्मक रूप से शब्दबद्ध नहीं है, पूर्ववर्ती धारा द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद प्रदान करती है, और पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करने में सक्षम बनाती है। इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य खंड खोज खंड जाए (ख) किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध को अभिसाक्ष्य दिया जाना चाहिए और उसके पश्चात् उतनी

जानकारी, जो उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित की जा सकती है।यह धारा इस विचार पर आधारित प्रतीत होती है कि यदि दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तव में किसी तथ्य का पता चलता है, तो इस प्रकार कुछ गारंटी दी जाती है कि जानकारी सही थी और तदनुसार साक्ष्य में सुरक्षित रूप से दिए जाने खंड अनुमति दी जा सकती है लेकिन स्पष्ट रूप से स्वीकार्य जानकारी सीमा खोजे गए तथ्य खंड सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिससे ऐसी जानकारी संबंधित है। आम तौर पर धारा को तब लागू किया जाता है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति किसी छिपे हुए स्थान से कोई वस्तु, जैसे कि मृत शरीर, हथियार या आभूषण प्रस्तुत करता है, जिसका संबंध उस अपराध से बताया जाता है जिसका मुखबिर आरोपी है। क्राउन के लिए श्री मेगाव ने तर्क दिया है कि इस तरह के मामले में 'तथ्य की खोज' भौतिक वस्तु है और कोई भी जानकारी जो उस वस्तु से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित की जा सकती है।इस दृष्टिकोण के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना कि उसके द्वारा हत्या किए गए व्यक्ति का वह मृत शरीर है, यह कि प्रस्तुत हथियार वह है जिसका उसने हत्या करने में उपयोग किया था, या यह कि प्रस्तुत गहने डकैती में चोरी किए गए थे, सभी स्वीकार्य होंगे।यदि यह धारा 27 का प्रभाव है, तो पुलिस को दिए गए इकबालिया बयानों पर, या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा लगाई गई दो पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में बहुत कम सामग्री रह जाएगी। यह प्रतिबंध संभवतः विधायिका के डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में एक व्यक्ति को अनुचित दबाव के अभ्यास से कबूल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। किंतु यदि प्रतिबंध हटाने के लिए बाद में प्रस्तुत किसी उद्देश्य से संबंधित सूचना की संस्वीकृति में समावेशन ही अपेक्षित है, तो यह मानना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि पुलिस की अनुनय शक्तियां इस अवसर के बराबर साबित होंगी और यह कि व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा।निर्माण के सामान्य सिद्धांतों पर उनके लार्डशिप्स (माननीय) का विचार है कि धारा द्वारा जोड़े गए धारा 26 के परंतुक को खंड के सार को अमान्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।उनके लार्डशिप्स (माननीय) के विचार में खंड के भीतर "खोजे गए तथ्य" को प्रस्तुत वस्तु के समतुल्य मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु को प्रस्तुत किया गया

है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तुत वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है।हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई यह जानकारी कि मैं अपने घर की छत में छुपा कर रखे गए चाकू का उत्पादन करूंगा, 42 तक नहीं ले जाती है. कई साल पहले चाकू और चाकू की खोज की गई थी।इससे इस तथ्य का पता चलता है कि एक चाकू मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार छिपा हुआ है और यदि यह साबित हो जाता है कि चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया था, तो यह तथ्य बहुत प्रासंगिक है।लेकिन यदि कथन के साथ शब्द जोड़े जाएं, जिससे मैंने ए को छुरा मारा है, तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे मुखबिर के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।

45. मोहम्मद के मामले मेंइनायत बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 828, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि 'अभिव्यक्ति' उपबंध करती है कि 'चाहे वह संस्वीकृति के बराबर है या नहीं' वाक्यांश के साथ यह दर्शाता है कि यह धारा पूर्ववर्ती उपबंधों, विशेष रूप खंड धारा 25 और 26 के अपवाद की प्रकृति की है।इस मामले में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या यह धारा किसी भी हद तक धारा 24 के योग्य है। यह देखा जाएगा कि इस धारा को लागू करने के लिए पहली आवश्यक शर्त किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता लगाना है, हालांकि यह एक प्रासंगिक तथ्य है। दूसरा यह है कि इस तरह के तथ्य की खोज को खारिज किया जाना चाहिए।तीसरा यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मात्र उतनी ही सूचना स्वीकार्य है, जितनी कि इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है।शेष जानकारी को बाहर रखा जाना चाहिए।(जोर दिया गया है)

46. सलीम अख्तर उपनाम मोटा (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मत व्यक्त किया हैः-

जहां तक अपीलकर्ता के घोषित बयान का संबंध है, वह पुलिस कर्मियों के लिए स्वीकार किया गया था और बयान का केवल वह हिस्सा स्वीकार्य होगा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य के प्रसिद्ध मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा इस प्रावधान के दायरे को समझाया गया था।एम्परर, एआईआर (1947) पीसी 67 मामले में यह माना गया था कि धड़ा के भीतर खोजे गए तथ्य को उत्पादित वस्तु के समतुल्य मानना भ्रामक है।खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है और इस बारे में अभियुक्त का ज्ञान और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है।इसलिए, जो स्वीकार्य है, वह वह जगह है जहां से पिस्तौल और अन्य वस्तुओं से युक्त पॉलीथीन बैग कथित रूप से बरामद किया गया था।यह तथ्य कि किसी आतंकवादी संगठन ने अपीलकर्ता को पिस्तौल और अन्य सामग्री दी थी या इसका उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा.

47. इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के से दिए गए पाल सिंह के बयान का मात्र एक हिस्सा, जहां वह दावा करता है कि उसने सितंबर, 1992 के पहले सप्ताह में गाजियाबाद में अदालत के पास स्थित सर्विस स्टेशन में खंडवा के लिए कार ली थी और तथ्य यह है कि वह उक्त सर्विस स्टेशन की पहचान कर सकता है, पाल सिंह के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है।यद्यपि कार का पिछला इतिहास, या कथित अपराध में इसके उपयोग को अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में पाल सिंह के प्रकटीकरण बयान के एक हिस्से को पढ़ते हुए कानून को गलत तरीके से लागू है । इस न्यायालय के समक्ष अंतिम मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120-बी से अपराध स्थापित करने में सफल हुआ है या नहीं?

49. भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120 ख निम्नानुसार हैः- आपराधिक षड्यंत्र का दंड-

(1) जो कोई मृत्यु, 2 [आजीवन कारावास] या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है, जहां ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया हो।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप में दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

50. न्यायिक आदेश के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैंः- (i) दो या अधिक व्यक्तियों के बीच करार,(ख) ऐसा कोई कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं है बल्कि अवैध साधनों से किया गया है।

51. राज्य बनाम नलिनी [(1999) 5 एस. सी. सी. 253] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में आपराधिक षड्यंत्र के मामले को शासित करने वाले सिद्धांतों को अधिकथित किया हैः-

षड्यंत्र की विधि को शासित करने वाले कुछ व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक सारांश सिद्धांतों का संपूर्ण नहीं हो सकता है।

1. भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120 ए के तहत आसोधिक षड्यंत्र का असोध तब किया जाता है जब दो या अधिक व्यक्ति ऐसा करने या ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं (क) अवैध साधनों द्वारा कोई अवैध कार्य या विधिक कार्य करना.जब यह अवैध साधनों द्वारा कानूनी कार्य हो तो प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक है।आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सामान्य कानून का अपवाद है जहां केवल आशय ही अपराध नहीं है।यह अपराध करने और एक ही इरादे वाले व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाने का इरादा है।न मात्र आशय बल्कि आशय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहमति होनी चाहिए, जो एक अपराध है।एक मामले में विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या सभी

अभियुक्तों का इरादा था और क्या वे सहमत थे कि अपराध किया जाए।षड्यंत्र के अपराध के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि कुछ अभियुक्तों ने मात्र यह इच्छा व्यक्त की हो कि अपराध किया जाए, भले ही यह कितना ही भयावह क्यों न हो।

2. षड्यंत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के पश्चात् किए गए अधिनियमों से यह साबित करने की प्रवृत्ति हो सकती है कि कोई विशिष्ट अभियुक्त षड्यंत्र का पक्षकार था।एक बार षड्यंत्र का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद कोई भी अनुवर्ती कार्य, जो गैरकानूनी हो सकता है, अभियुक्त को किसी फ़रारी को आश्रय देने के समान षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बना सकता।

षड्यंत्र निजी रूप से या गोपनीय रूप से किया जाता है।प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा षड्यंत्र स्थापित करना शायद ही कभी संभव होता है।आमतौर पर, षड्यंत्र के अस्तित्व और उसके उद्देश्यों दोनों का अनुमान अभियुक्त की परिस्थितियों और आचरण से लगाया जाता है।

उदाहरण के लिए, षड्यंत्रकारियों को ए नामांकन बी, बी नामांकन सी आदि में नामांकित किया जा सकता है और यदि वे ऐसा इरादा रखते हैं और सहमत होते हैं तो सभी एकल षड्यंत्र के सदस्य होंगे, भले ही प्रत्येक सदस्य मात्र उस व्यक्ति को जानता है जिसने उसे नामांकित किया है और वह उस व्यक्ति को जानता है जिसे वह नामांकित करता है।एक प्रकार का अम्ब्रेला-स्पोक नामांकन हो सकता है, जहां केंद्र में एक व्यक्ति नामांकन कर रहा है और अन्य सभी सदस्य एक-दूसरे से अनजान हैं, हालांकि वे जानते हैं कि अन्य सदस्य होने चाहिए।ये सिद्धांत हैं और व्यवहार में यह कहना मुश्किल हो सकता है कि किसी विशेष मामले में साजिश किस श्रेणी में आती है।यद्यपि यह ओवरलैप भी हो सकता है।लेकिन इसके बाद परस्पर हित प्रस्तुत करना होगा।व्यक्ति एकल षड्यंत्र के सदस्य हो सकते हैं, भले ही प्रत्येक को कई अन्य लोगों की पहचान के बारे में पता न हो, जो अलग-अलग भूमिका निभा सकते हैं।यह साजिश के अपराध का हिस्सा नहीं है कि सभी साजिशकर्ताओं को समान या सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है।

5. जब दो या अधिक व्यक्ति षड्यंत्र का अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसके लिए कोई योजना बनाने या विचार करने की परवाह किए बिना और इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा कोई व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक अपराध किया जाता है जो करार में शामिल होता है।इस प्रकार दो साजिशकर्ता होने चाहिए और इससे अधिक हो सकता है।साजिश के आरोप को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इरादा अपराध किया गया था या नहीं।यदि ऐसा किया अग्रेतर है तो यह षड्यंत्र के आरोप को साबित करने में अभियोजन पक्ष की मदद कर सकता है।

6. यह आवश्यक नहीं है कि सभी षडयंत्रकारी एक ही समय में समान उद्देश्य के लिए सहमत हों।वे इरादा पूरा होने से पहले किसी भी समय अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हो सकते हैं । और सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं।प्रत्येक षड्यंत्रकारी को क्या भूमिका निभानी है, यह सभी को ज्ञात नहीं होगा या यह तथ्य कि षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में कब शामिल हुआ और वह कब चला गया।

7. षड्यंत्र का आरोप अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है क्योंकि उसे संयुक्त विचारण के लिए मजबूर किया जाता है और विचारण प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार कर सकता है।अभियोजन को न मात्र यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रत्येक अभियुक्त को साजिश के उद्देश्य की जानकारी है, बल्कि समझौते की भी जानकारी है।षड्यंत्र के आरोप विरुद्ध न्यायालय को अभियुक्त के प्रति अन्याय के खतरे से स्वयं की रक्षा करनी होती है।कुछ के विरुद्ध सबूत पेश करने से सभी को दोषी ठहराया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है। षड्यंत्र में साक्ष्य के माध्यम से, जो अन्यथा किसी अन्य मूल अपराध के विचारण में अस्वीकार्य है, अभियोजन न मात्र षड्यंत्र में बल्कि कथित षड्यंत्रकारियों के मूल अपराध में भी अभियुक्त को फंसाने का विचारण करता है।साजिश के प्रत्येक सदस्य के सटीक योगदान का पता लगाने में हमेशा कठिनाई होती है, लेकिन फिर साजिश के अपराध में आरोपित प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय सबूत होना चाहिए।"जैसा कि न्यायाधीश विद्वान हैंड देखा कि "यह अंतर आज महत्वपूर्ण है जब

कई अभियोजक उन सभी को साजिश के जाल में झाड़ना चाहते हैं जो मुख्य अपराधियों के साथ किसी भी हद तक जुड़े हुए हैं"।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह गैरकानूनी समझौता है, न कि इसकी उपलब्धि, जो साजिश के अपराध का सार या सार है।आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पूरा हो जाता है, भले ही इस बारे में कोई सहमति न हो कि उद्देश्य किस माध्यम से पूरा किया जाना है।यह गैरकानूनी समझौता है, जो षड्यंत्र के अपराध की कद्र है।गैरकानूनी समझौता जो एक साजिश के बराबर है, वह औपचारिक या व्यक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों, विशेष रूप से घोषणाओं, कार्यों और साजिशकर्ताओं के आचरण में अंतर्निहित और अनुमानित हो सकता है।सभी पक्षों द्वारा एक ही समय में समझौता किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साजिश में उनके शामिल होने के सबूत के रूप में एक के बाद एक कार्रवाई की जा सकती है।

9. यह कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र अपराध में भागीदारी है और प्रत्येक षड्यंत्र में एक साझा योजना के अभियोजन के लिए एक संयुक्त या पारस्परिक अभिकरण है। इस प्रकार, यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्र में लिप्त होते हैं तो करार के अनुसरण में उनमें से किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य कानून के अनुसार उनमें से प्रत्येक का कार्य है और वे इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।इसका अर्थ यह है कि किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा निष्पादन या सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कही गई, की गई या की गई हर बात को उनमें से प्रत्येक द्वारा कहा गया, किया गया या लिखा गया माना जाता है।और यह संयुक्त उत्तरदायित्व न मात्र मूल समझौते के अनुसार किसी भी साजिशकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई पर लागू होती है, बल्कि मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपार्श्विक कार्य भी करती है।षडयंत्र समाप्त यद्यपि पश्चात सह-षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक षड्यंत्रकारी जिम्मेदार नहीं है।एक नए सदस्य द्वारा साजिश में शामिल होने से न तो कोई नई साजिश पैदा होती है और न ही इससे अन्य साजिशकर्ताओं की स्थिति में कोई बदलाव आता है, और केवल यह तथ्य कि साजिशकर्ता व्यक्तिगत रूप से या समूहों का प्रदर्शन करते हैं एक समान

उद्देश्य के लिए विभिन्न कार्य एक साजिश को कई अलग-अलग साजिशों में विभाजित नहीं करते हैं।

10. कोई व्यक्ति अपनी वाणी या कर्म से किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। यद्यपि किसी षड्यंत्र के लिए आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए किसी मौजूदा षड्यंत्र के प्रति मात्र निष्क्रिय दृष्टिकोण से अधिक की आवश्यकता होती है।जो व्यक्ति षड्यंत्र की जानकारी के साथ कोई प्रत्यक्ष कार्य करता है वह दोषी है।और जो कोई षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए मौन रूप से सहमति देता है और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ चला जाता है, वास्तव में खड़ा है जबकि अन्य षड्यंत्रकारी षड्यंत्र को लागू करते हैं, वह दोषी है, हालांकि वह अपराध में कोई सक्रिय भाग नहीं लेना चाहता है।

52. अपीलकर्ता के विरुद्ध पूरा अभियोजन मामला अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक आपराधिक षड्यंत्र के अस्तित्व के संबंध में सफेद मारुति कार के खूंटे पर टिका हुआ है।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उक्त कार अपीलकर्ता द्वारा खरीदी गई थी, और महेंद्र सिंह भाटी की कथित हत्या करने के लिए करण यादव और पाल सिंह को दी गई थी.

53. यद्यपि नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) के दूसरे कथन (एक्स. का. 114) और सह-अभियुक्त व्यक्तियों में से एक पाल सिंह के प्रकटन कथन (एक्स. का. 113) के लिए, अपीलकर्ता और सफेद मारुति कार के बीच कोई संबंध स्थापित करने के लिए अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का एक अंश भी नहीं है।लेकिन जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, न तो नारायण यादव (पी डब्लू 37) का दूसरा बयान (एक्स. का. 114), और न ही पाल सिंह का प्रकटीकरण बयान (एक्स. का. 113) अपीलकर्ता के विरुद्ध पढ़ा जा सकता है. वास्तव में, जहां तक कार का संबंध है, अभियोजन ने आधे पकाए हुए व्यंजन का उत्पादन किया है।

54. इसके लिए अनिल कुमार भाटी (पी डब्ल्यू 39) ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सात से आठ हमलावर मारुति कार में फरार हो गए।लेकिन वो न तो गाड़ी का रंग देता है और न ही उसका नंबर देता है।अन्य प्रत्यक्षदर्शियों मात्र अदालत को बताया कि दो हमलावर एक कार में फरार हो गए।यहां तक कि वे न तो कार का निर्माण करते

हैं, न कार का रंग, न ही उसका पंजीकरण नंबर प्रकट करते हैं।इसके अग्रेतर मीनाक्षी सैनी (पीडब्लू 17) के अनुसार, कार मूल रूप से कुणाल कपूर के स्वामित्व में थी। लेकिन अभियोजन पक्ष ने गवाह के रूप में कुणाल कपूर की जांच नहीं की है।नारायण यादव (पी डब्लू 37) के दूसरे बयान (एक्स. का. 114) में ही पहली बार कार का रंग और पंजीकरण संख्या दोनों का खुलासा किया गया मात्र।उनके अनुसार, कार सफेद रंग की थी, जिस पर पंजीकरण संख्या डीएल 4 सीबी 3597 था।यद्यपि इसमें ऊपर बताए गए कारणों से, कथित बयान (एक्स. का. 114) को अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है । यहां तक कि पाल सिंह का प्रकटीकरण बयान (एक्स. का. 113) जिसमें वह दावा करता है कि सफेद मारुति कार अपीलकर्ता द्वारा दी गई थी, यहां तक कि यह बयान भी अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है.

55. अभियोजन पक्ष ने कार की जब्ती के संबंध में दो गवाहों जगदीश सिंह यादव (पी डब्ल्यू 36) और नवीन चंद्र झा (पी डब्ल्यू 41) से पूछताछ की है।यहां तक कि उनकी गवाही से भी भ्रम पैदा होता है।जगदीश सिंह यादव (पी. डब्ल्यू. 36) के अनुसार, उसने एक कार 49 बरामद की थी पंजीकरण संख्या यूईयू 5004 के साथ और प्रदर्शनी का-97 के रूप में चिह्नित वसूली ज्ञापन तैयार किया था।यद्यपि अभियोजन पक्ष के अनुसार, सफेद मारुति कार में पंजीकरण संख्या डीएल 4 सीबी 3597 था।इसलिए, एक सफेद मारुति कार की बरामदगी, जिस पर पंजीकरण संख्या यूईयू 5004 है, अप्रासंगिक है।

56. नवीन चंद्र झा (पीडब्लू 41) के अनुसार, उसने एक कार बरामद की थी, जिसकी पंजीकरण संख्या डीएल 4 सीबी 3597 थी।यद्यपि उक्त वसूली के संबंध में कभी भी कोई वसूली ज्ञापन नहीं बनाया गया था।इसके अलावा, इस गवाह के अनुसार, उसने 16.07.1996 को गुरदीप सिंह से कार जब्त कर ली थी।यद्यपि अपनी जिरह में इस गवाह ने दावा किया कि उसने कभी कार जब्त नहीं की।वास्तव में वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि सीबीआई अधिकारी कौन था, जिसने वास्तव में कार को जब्त किया था।इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथित कार की वसूली का कोई ज्ञापन नहीं है । दिलचस्प

बात यह है कि उक्त कार का कभी भी एक भौतिक वस्तु के रूप में उत्पादन नहीं किया गया है।इसके अलावा न तो कार के मूल मालिक कुणाल कपूर और न ही कार के अंतिम मालिक गुरदीप सिंह से अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में पूछताछ की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने के लिए कि कार कभी भी अपीलकर्ता द्वारा खरीदी गई थी, या कथित घटना से पहले उसके कब्जे में थी, एक छोटा सा सबूत पेश करने में बुरी तरह से विफल रहा है.इसलिए 50 प्रतिशत कार को अपीलकर्ता से जोड़ने वाले साक्ष्य का एक टुकड़ा भी नहीं है.

57. एक बार अभियोजन का मुख्य आधार टूट जाने के बाद, अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच अवैध कार्य करने के लिए कोई समझौता था।इसके अलावा, अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि सह-साजिशकर्ताओं के बीच ऐसा कोई अपराध करने का कोई इरादा था, जिसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया था।इसलिए, अभियोजन अपीलकर्ता और कथित हमलावरों और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक साजिश के अपराध को साबित करने में विफल रहा है।इसलिए, भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 120 बी के साथ पठित खंड 302 , भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 307 और भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 326 के से अपराध अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं बनाया गया है ।

58. जैसा भी मामला सनसनीखेज या जघन्य हो, विचारण न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह किसी अभियुक्त व्यक्ति के दोष या निर्दोषिता के बारे में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व साक्ष्य की आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से जांच करेगा। तथ्यों और सबूतों के बीच पूरे संबंध की कल्पना मात्र अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है । पहली बार में, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन एक विस्तृत महत्वपूर्ण विश्लेषण अन्यथा साबित हो सकता है। इस प्रकार, यह क्या विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के प्रत्येक स्तर का व्यवस्थित और

आलोचनात्मक विश्लेषण करे कि क्या अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं?

59. वर्तमान मामले में, शुरुआत से ही, शिकायतकर्ता अनिल भाटी (पीडब्लू 39) द्वारा प्राथमिकी में अपीलकर्ता का नाम नहीं दिया गया है.दरअसल, शिकायतकर्ता के अनुसार, शुरू में उसने दावा किया था कि सात से आठ लोग थे, जिन्होंने मृतक पर हमला किया था।फिर भी, अदालत के समक्ष अपनी गवाही में, उसने दावा किया कि मात्र दो व्यक्तियों ने मृतक महेंद्र सिंह भाटी पर हमला किया था।अपनी शिकायत और सीआरपीसी की धारा 161 के से दिए गए अपने बयान में उन्होंने दावा किया था कि हमलावरों ने चिल्लाकर कहा था कि अब प्रकाश पहलवान को चुनाव लड़ने का प्रयास करें।इस प्रकार, कथित हत्या के उद्देश्य का संकेत देते हुए भी, अदालत के समक्ष अपनी गवाही में, वह मृतक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या की कथित साजिश के पीछे के उद्देश्य के बारे में एक भी शब्द नहीं कहता है.इसके अलावा, इस तथ्य के बावजूद कि अभियोजन पक्ष ने सतबीर गुर्जर और महेंद्र सिंह फौजी के गिरोहों के बीच मौजूद गिरोह युद्ध के बारे में लगातार दुष्प्रचार किया है, इस तथ्य के बावजूद कि कई आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से किसी भी एफआईआर में अपीलकर्ता कभी शामिल नहीं है।यहां तक कि एक प्राथमिकी में भी, जहां उनका नाम था, एक मामले में, उसके विरुद्ध आरोप-पत्र भी दायर नहीं किया गया था। प्राथमिकी में मात्र, जिसमें अपीलार्थी की बहन घायल हुई थी, यहां तक कि कथित मामला मात्र महेंद्र सिंह भाटी की कथित हत्या के पश्चात ही हुआ था । इस प्रकार, यहां तक कि कथित प्राथमिकी भी मृतक, महेंद्र सिंह भाटी से छुटकारा पाने के लिए अपीलकर्ता के उद्देश्य का आधार नहीं बन सकती है ।

60. यद्यपि यह सच है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य अपना महत्व खो देता है, किंतु जब कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा गया अभिकथित किया जाता है, तो उद्देश्य एक सुसंगत कारक होता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।आखिरकार आपराधिक साजिश तब तक नहीं रची जाती जब तक कि लोगों का एक समान इरादा न हो, जो उन्हें अपराध के लिए एक उद्देश्य तैयार करपश्चात के लिए प्रेरित करता है।

वर्तमान मामले में अंतिम उद्देश्य स्पष्ट रूप से गायब है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 से अभिलिखित कथन के उपयोग मात्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से अपीलकर्ता द्वारा दिए विद्वान कथन के उपयोग के संबंध में, दोनों के संबंध में गलत विधि लागू की है।लेकिन इन बयानों के उपयोग से, विद्वान विचारण न्यायालय स्वयं इंग्लैंड के राजा से अधिक निष्ठावान प्रतीत होता है.विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अभियोजन पक्ष के मामले को एक सत्य के रूप में प्रतिग्रहण करना करे।जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया विद्वान है, इसके बजाय विद्वत विचारण न्यायालय है । आशा की जाती है कि अभियोजन पक्ष के मामले का विश्लेषण और विश्लेषण एक अच्छे टूथकंघी से किया जाएगा।

62. विद्वान विचारण न्यायालय भी यह ध्यान देने में विफल रहा है कि उद्देश्य, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।इसके अलावा, विचारण न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रही है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार के चालक धर्मवीर और एक अन्य धर्मवीर सिंह, जो अपनी साइकिल पर था, जो मृतक व्यक्तियों पर कथित गोलीबारी के दौरान घायल हो गया था, को भी पेश नहीं किया गया है।इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा नामित गवाहों से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल मालिक कुणाल कपूर और अंतिम मालिक गुरदीप सिंह से भी गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है। चूंकि अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण गवाहों को रोक रखा है, इसलिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।फिर भी, विद्वान विचारण न्यायालय ऐसा करने में विफल रही है.अंत में, अपीलकर्ता के विरुद्ध पूरी दोषसिद्धि अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है.यह ऐसा कोई आधारभूत आधार नहीं है जिसे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित किया जा सके।वास्तव में, यह कहना कठिन है कि दोषसिद्धि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए।अन्यथा, दोषसिद्धि कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक है।कानून का शासन नैतिक विश्वास की अनुमति नहीं देता है।

63. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है।देहरादून के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (सी. बी. आई.) द्वारा दिनांक 10.03.2015 को पारित निर्णय को अपीलकर्ता को अपास्त जाता है।इसलिए, अपीलकर्ता को भारतीय जमानत भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 120-बी, भारतीय जमानत भा.दं.सं. की धारा 307 के साथ पठित धारा 120-बी और भारतीय जमानत भा.दं.सं. की धारा 326 के अपराधों से बरी किया जाता है।

(आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति) (राघवेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश)

10.11.2021

राठौर